livelihood is getting adversely affected. In this regard, our hon'ble Chief Minister Shri Naveen Patnaik has written to the Central Government, and had requested the latter to completely withdraw the 18 per cent GST on Kendu leaf in the larger interests and welfare of the tribals of Odisha. Therefore through you, I urge upon the Government to consider these three demands sincerely, and include Ho, Mundari, Bhumij, Saora and Kui in the Eighth Schedule of the Indian Constitution. Secondly, it is requested that the pending issue of including 169 tribal communities of Odisha in the ST list of Odisha be also considered. Thirdly, the present 18 per cent GST, which has been imposed on Kendu leaves, may be withdrawn completely. Our leader and Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has been persistently endeavoring in this regard, and we are hopeful that the Government will look into the matter in due earnestness."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sasmit Patra: Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Sujeet Kumar (West Bengal), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Now, Shri Nagendra Ray to raise the issue of fencing on Bangladesh Border.

Issue of fencing on Bangladesh border

श्री नगेन्द्र रॉय (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापित जी, मैं भारत एवं बंगलादेश के बॉर्डर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर, बड़े दुख की बात है कि हमारे बंगलादेश बॉर्डर पर illegal migrants होते हैं, जो इंडिया में आकर वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं। हमने सुना है कि तृणमूल के लीडर्स बंगलादेश के नागरिकों को इंडिया में लाकर वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाते हैं। ऐसा लगता है कि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं। यह जो activity हो रही है, वह anti social activity चल रही है, इससे भारत को बहुत खतरा है। यह इसलिए हो पा रहा है कि unfenced इलाके में दिन-दहाड़े लोग इंडिया में घुस जाते हैं। जैसे cattle smuggling होती है, जब भी Border Security Force invisible होती है, तब यह ज्यादा होता है। बॉर्डर पर हज़ारों लोग इकट्ठे होकर यह काम करते हैं। बॉर्डर पर जो unfenced इलाका है, मैंने वहां पर जाकर देखा और मैंने बीएसएफ के कमांडर को पूछा कि यह unfenced क्यों है, तो वह बोलता है कि वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट land allotment नहीं कर रही है। छह साल से land allotment नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर fencing नहीं हो पा रही है, जैसे smuggling नहीं रुक रही है। तब मैंने उनसे पूछा कि आपने गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं की। वे बोले कि हम लोगों ने डीएम साहब से बात की, लेकिन there was no response. फिर मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब के ऑफिस में गया और मैंने उनसे मिलना चाहा, लेकिन उन्होंने deny कर दिया कि

मैं काम में व्यस्त हूं। उन्होंने कहा कि आप एडीएम से मिलिए। उसके बाद मैंने एडीएम से बात की और उन्हें बता दिया की fencing का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि देखते हैं। सर, अगर इस तरह से चलता रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? हमारी वैस्ट बंगाल पुलिस ने बंगलादेशी को पकड़ा। It is very dangerous. यह हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी हालत में यह जल्द से जल्द रुकना चाहिए? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द वैस्ट बंगाल सरकार land allot कर दे।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपका समय समाप्त हो गया है, धन्यवाद। माननीय श्री सतीश चंद्र दूबे जी। ...(व्यवधान)... Nothing is going on record. ...(Interruptions)...

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Nagendra Ray: Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra) and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

Now, Shri Satish Chandra Dubey on 'demand to start railway services between Chhitauni and Tamkhui in Bihar.'

Demand to start railway services between Chhitauni and Tamkhui in Bihar

श्री सतीश चंद्र दूबे (बिहार): उपसभापित महोदय, वर्ष 2007 में छितौनी तमकुही रेल लाइन का शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा किया गया था। रेल लाइन पनियहवा से छितौनी होते हुए, नारायणी नदी के किनारे होते हुए बिहार प्रांत के मधुबनी, धनहा, खैरा टोला इत्यादि स्थानों से होकर गुजरेगी तथा कुशीनगर के तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर यह कप्तानगंज-थावे रेल लाइन में मिल जाएगी।

वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक जब मैं लोक सभा का सदस्य था, तब मैंने अनेक बार पत्राचार किया और सदन में आवाज उठाई। इसके लिए धनराशि स्वीकृत भी की गई और कुछ कार्य भी हुए, लेकिन अभी तक इसमें कुछ ठोस कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारियों से वार्ता करने के बाद बताया गया कि धन के अभाव में कार्य पूरा नहीं हो रहा है। इस रेल लाइन के निर्माण से नारायणी नदी के इस पार स्थित बिहार के निवासियों के लिए बड़ी राहत होगी, उन्हें आवागमन की अच्छी सुविधा सुलभ हो जाएगी और इसके साथ ही हर साल आने वाली बाढ़ से भी स्थायी तौर पर बचाव होगा। हमारा चम्पारण सत्याग्रह की धरती है और वहां के लोग आज भी चार ब्लॉक की रेल से वंचित हैं। इस रेल लाइन से बहुत उम्मीदें हैं।

अतः आपसे नम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस रेल लाइन को अधिक से अधिक धनराशि देकर पूर्ण करवाया जाए। उपसभापित महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस रेल लाइन को धन देकर निश्चित रूप से इसका कार्य पूरा कराया जाए, क्योंकि यह गांधी जी के सत्याग्रह की धरती है और चम्पारण का यह बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। अतः आपसे आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक धन देकर कम समय के अंदर पूरा करवाया जाए।